

प्रेषक,

एन०एस० नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक,
पंचायतीराज निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज अनुभाग:

विषय:- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०) के अन्तर्गत क्षमता विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में
धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

देहरादून

दिनांक ०४ जून, 2012

उपर्युक्त विषयक, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-N-11019/452 /07-Pol-I(III) दिनांक 31-03-2012 तथा पत्र संख्या- N-11019/452 /07-Pol-I(I) दिनांक 31-03-2012 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०) के अन्तर्गत क्षमता विकास हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त योजनान्तर्गत पत्र सं० N-11019/452 /07-Pol-I(III) द्वारा रु० 1.65 करोड़ सामान्य अंश में तथा पत्र सं० N-11019/452 /07-Pol-I(I) द्वारा रु० 0.34 करोड़ अनुसूचित जाति अंश में अर्थात् कुल धनराशि रु. 1.99 करोड़ (रु. एक करोड़ नियनवे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्राविधानित धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की निम्न प्रतिबन्धों के अधीन श्री महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग योजना आयोग भारत सरकार द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के लिये निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

3- उक्त आवंटित धनराशि को ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, तो ऐसा व्यय, स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये। स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों/मार्ग निर्देशक सिद्धान्त के अनुसार ही सुनिश्चित किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि की योजनावार आवंटन की सूचना शासन को एक माह के भीतर उपलब्ध करायी जाय धनराशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन, भारत सरकार एवं महालेखाकार को यथासमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायें।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्ण उपयोग कर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप पर शासन एवं योजना आयोग, भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- यह सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रौद्योरमेन्ट रूल्स, 2008 तथा भारत सकरार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों (योजना की गाइड लाईन्स) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित जनपद के कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक माह की 25 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही कार्य की प्रगति से समय समय पर शासन को अवगत कराया जाए।

8- बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर परचेज रूल्स, डी०जी०एस०एन०डी० की दरें अथवा टेन्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

9- वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अब तक की अवशेष राशि व वर्तमान में दी जा रही धनराशि का शत प्रतिशत उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

10- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुदान संख्या 19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-01-केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्रपुरोनिधानित योजना-104-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि-42-अन्य व्यय से रु. 1.65 करोड़ (रु. एक करोड़ पैंसठ लाख मात्र), अनुदान संख्या 30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा केन्द्रपुरोनिधानित योजनायें -0101-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान-42-अन्य व्यय से रुपये 0.34 करोड़ (रु. चाँतीस लाख मात्र) की धनराशि सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 27(P)/XXVII(4)/2012, दिनांक 21 जून, 2012 द्वारा प्राप्त निर्देशों अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन०एस० नेगी)
सचिव।

संख्या ६६५ (1) / XII / 2012 / 82(1) / 2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स विल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. निदेशक, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को माठ मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. श्री एल०एम० पन्त, अपर सचिव, वित्त, बजट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून / वित्त-1।
8. विभागीय पत्रावली / समन्वयक, एन०आई०सी०, सचिवालय, देहरादून / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Munni

(जे०एल० शर्मा)
अनु सचिव।

2